CC MM YY KK

RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

सम्माननीय जीवन समान अधिकार

केन्द्रीय मानवाधिकार दैनिक

| नागपुर. गुरुवार, 7 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 162 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु.

संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

चंद्रपुर राजस्व विभाग का मतलब 'सार्वजनिक सेवा' - डॉ. ऊइके

चंद्रपुर – आम नागरिकों के लिए सरकार का मतलब राजस्व विभाग है। कोतवाल से लेकर जिला कलेक्टर तक, आम नागरिकों के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में समर्पण की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए, उनके काम में पारदर्शिता, गति और जनोन्मुखी होना आवश्यक है। राजस्व विभाग केवल प्रशासन का एक अंग नहीं है, यह 'लोकसेवा का सच्चा प्रतिनिधि' है। इसलिए, राजस्व विभाग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को हमेशा निष्ठा, पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए और नागरिकों के काम समय सीमा के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक ऊइके ने व्यक्त की। जिले में 1 से 7 अगस्त तक मनाए जा रहे राजस्व सप्ताह के अवसर पर एक बधाई पत्र में पालकमंत्री डॉ. वुइके ने कहा, राजस्व विभाग प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र माना जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, नीतियों, आदेशों और कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। 'गांव से राजधानी' तक व्यापक कार्यक्षेत्र वाला यह विभाग सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। अक्सर 'राजस्व' शब्द का अर्थ केवल वित्तीय आय से जुड़ा होता है। लेकिन, वास्तव में, यह विभाग भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने, नामांतरण दर्ज करने, कृषि क्षति का पंचनामा, सामाजिक सहायता योजनाएं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और चुनाव जैसे कई कार्यों में शामिल होता है। सही मायने में, राजस्व विभाग सरकारी व्यवस्था की रीढ़ है। पिछले कुछ वर्षों में, राजस्व विभाग ने डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं, ई-सातबारा, ई-फेरफार, मोबाइल ऐप, नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से आसान, पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। यह एक सकारात्मक बदलाव है क्योंकि नागरिकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। चंद्रपुर जिले में वनों की प्रचुरता और वन विभाग तथा राजस्व विभाग के बीच उचित समन्वय के कारण, वनाधिकार, वनों की कटाई, झाड़ी भूमि के रूपांतरण, वनरोपण हेतु आवश्यक भूमि के क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य प्रगति पर हैं। इसमें राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही, चंद्रपुर जिले में वन भूमि की प्रचुरता होने के कारण, यहाँ के पारंपरिक आदिवासी समुदाय के वनाधिकार दावों को स्वीकृत किया गया और उनकी भूमि को खेती के लिए उपलब्ध कराया गया। इससे पीढ़ियों से उपेक्षित आदिवासी समुदाय विकास की मुख्यधारा में आ गया है। राजस्व विभाग के माध्यम से ही सरकार की विभिन्न योजनाएँ समाज के अंतिम तबके तक पहुँचती हैं।

'उम्मेद मॉल' महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय सशक्तिकरण का मार्ग - मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए एक स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए 'उम्मेद मॉल' (जिला बिक्री केंद्र) स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने विश्वास व्यक्त किया है कि इसका सीधा लाभ महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण में होगा। इस पहल के तहत पहले चरण में 10 जिलों में उम्मेद मॉल स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये मॉल 'उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका उत्थान मिशन' के तहत संचालित होंगे। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। ये मॉल स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थों, कपड़ों और अन्य उत्पादों के लिए स्थानीय बाज़ार उपलब्ध कराएँगे। मंत्री गोरे ने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष बिक्री से उत्पादकों को अच्छा मुनाफ़ा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विभाग के माध्यम से प्रदर्शनी, ई-कॉमर्स पोर्टल (उम्मेद मार्ट) और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी प्रकार, इन मॉल्स में भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फ़ॉर लोकल' की अवधारणा को मज़बूत करते हुए, ये विक्रय केंद्र स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। पहले चरण में जिन दस ज़िलों में मॉल स्थापित किए जाएँगे, उनके बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मंत्री गोरे ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति में निश्चित रूप से तेज़ी आएगी।

केंद्र ने बंगाल के विकास के लिए 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा दिए –शिवराज

कोलकाता – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास, गांव-गरीब और मजदूरों के कल्याण तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही पश्चिम बंगाल को 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के जरिये दी गई है। चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 16,505 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 25,798 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और आरएसईटीआई के तहत 274 करोड़ रुपये, मनरेगा (2014-15 से 2022 तक) के तहत 54,465 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में 3,881 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 8,389 करोड़ रुपये सीधे पश्चिम बंगाल के गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के गांव, गरीब और मजदूरों के जीवन में परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वह पक्का घर हो, सड़क हो, आजीविका या रोज़गार हो।

शिवराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में बुरी तरह विफल रही है। 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। इनमें कार्यस्थल पर वास्तविक कार्य न होना, नियम विरुद्ध कामों को हिस्सों में तोड़ना, धन की हेराफेरी जैसी गंभीर बातें उजागर हुईं। इसी के चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा अधिनियम की धारा 27 के तहत पश्चिम बंगाल का फंड रिलीज़ करना रोकना पड़ा है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी शिकायतें मिलीं कि राज्य सरकार ने अपात्र परिवारों का चयन किया, पात्रों को हटाया और योजना का नाम बदलकर नियमों की अनदेखी की। ये सारी शिकायतें राष्ट्रीय और केंद्रीय मॉनिटरिंग टीमों द्वारा सही पाई गईं।

चौहान ने बताया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुधार या पारदर्शिता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। दुर्भाग्यवश, पश्चिम बंगाल सरकार विश्वास, जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के विकास, कल्याण और अधिकारों के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी।

'व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025' पारित

लोकसभा से आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति के लिए 'व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025' पारित होने के साथ भारत ने समुद्री ढाँचे को अद्यतन किया। राज्यसभा ने व्यापार सुगमता और भारत के पोत परिवहन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु 'समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025' पारित किया। संसद ने ऐतिहासिक घटनाक्रम में बुधवार को दो ऐतिहासिक समुद्री विधेयक पारित किए। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के लिए यह पहला विधेयक है। इससे भारत में आधुनिक, कुशल और वैश्विक स्तर पर समन्वित समुद्री नीति ढाँचे का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोकसभा ने 'व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025' को स्वीकृति दे दी। इसका उद्देश्य आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन दृष्टिकोण के साथ समुद्री शासन को सुव्यवस्थित करना है। इस बीच, राज्यसभा ने 'समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025' पारित किया। इसने एक सदी पुराने औपनिवेशिक युग के कानून को व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और भारत के नौवहन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु डिज़ाइन किए गए अद्यतन कानून से बदल दिया।

इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "आज मंत्रालय में हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों - व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 और समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 - को पारित किया है, जो नीतिगत और कार्यान्वयन दोनों दृष्टि से भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का प्रभावी ढंग से समर्थन करते हैं। आज, इन विधेयकों के पारित होने के साथ, भारत के आधुनिक पोत परिवहन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को संसद से दोहरा समर्थन प्राप्त हुआ है।" व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 - प्रगतिशील, भविष्य के लिए तैयार कानून जो पुराने व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। यह विधेयक भारत के समुद्री कानूनी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और विश्वसनीय समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लोकसभा में व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025 पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "यह विधेयक भारत को समुद्री व्यापार और प्रशासन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। यह प्रगतिशील और उन्नत कानून है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के अनुरूप है और अग्रणी समुद्री राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है।" यह विधेयक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किए गए प्रमुख कानूनी सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य शिपिंग और समुद्री क्षेत्रों में मजबूत विकास को सक्षम बनाना है। इन सुधारों ने दक्षता, पारदर्शिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अद्यतन ढाँचे की आवश्यकता पर बल देते हुए, मंत्री ने कहा कि व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 561 धाराओं के साथ भारी, खंडित और पुराना हो गया था, जो समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करने या कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहा। सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी कहा, "व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025, 16 भागों और 325 धाराओं के साथ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप भारत के समुद्री कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करता है, समुद्र में सुरक्षा बढ़ाता है।

स्मार्ट के तहत 79 किसानों के सीबीओ को 172.05 करोड़ रुपये

नागपुर – नागपुर संभागीय संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय के माध्यम से संभाग के 6 जिलों में कुल 79 किसान समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) स्वीकृत किए गए हैं। संभाग के वर्धा जिले में कुल 10 सीबीओ स्वीकृत किए गए हैं। इनमें नागपुर जिले में 15, भंडारा जिले में 11, गोंदिया जिले में 14, चंद्रपुर जिले में 22 और गढ़चिरौली जिले में 7 शामिल हैं। स्मार्ट के तहत इन परियोजनाओं के लिए 172.05 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और 103.02 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया। इससे पहले, विश्व बैंक (आईबीआरडी) की सहायता से राज्य में दो परियोजनाएँ, "महाराष्ट्र प्रतिस्पर्धी कृषि विकास परियोजना" और "महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन" सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई थीं। इसी आधार पर, विश्व बैंक ने स्मार्ट परियोजना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्मार्ट परियोजना के अंतर्गत, किसान उत्पादक समूहों के गठन और उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़ा जा रहा है, फसलोत्तर प्रबंधन और कृषि उपज के प्राथमिक प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य उत्पादन में मदद की जा रही है और इन सभी पहलों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करके उनके लिए आजीविका का स्रोत तैयार किया जा रहा है। यह योजना विश्व बैंक और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के कृषि और ग्रामीण आजीविका क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों को लागू करके राज्य का कायाकल्प करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 70% विश्व बैंक, 27% राज्य सरकार और 3% निजी क्षेत्र (सीएसआर) द्वारा प्रदान किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 2,100 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का क्रियान्वयन कृषि, पशुपालन, विपणन, सहकारिता, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास और शहरी विकास जैसे सात प्रशासनिक विभागों की ग्यारह एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

नागपुर जिला योजना भवन में समीक्षा बैठक

नागपुर – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिला वार्षिक योजना के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के विचार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिए जाने चाहिए। जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई गई निधि से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इससे नवीन योजनाएं आकार लेती हैं। इन कार्यों से विभिन्न स्थानों पर स्थित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष

रूप से स्वरोजगार का सृजन होता है। जिला वार्षिक योजना में कार्यों का निर्धारण करते समय, जिन क्षेत्रों में ये कार्य प्रस्तावित हैं, वहां के विभागाध्यक्ष विचार प्रस्तुत करें और कार्यों का प्रस्ताव रखें, ऐसा निर्देश राज्य के राजस्व मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया।

वे जिला नियोजन भवन में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। बैठक में मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपुर सुधार न्यास के अध्यक्ष संजय मीना, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उचित सावधानी बरतें और जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत जिन विभागों को धनराशि हस्तांतरित की गई है, उन्हें सरकारी निर्णय के अनुसार 15 अगस्त तक हर हाल में उन योजनाओं के लिए धनराशि का व्यय पूरा करें। हमने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता ली है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी आम लोगों तक आसानी से पहुँचे और एक जनोन्मुखी प्रशासन हो। उन्होंने कहा कि सबके लिए आवास एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, नागपुर सुधार ट्रस्ट, जिला परिषद को आपस में समन्वय स्थापित कर भूमि वितरण अभियान को और गति देने की आवश्यकता है।

आने वाले दिनों में, सभी की भक्ति का गणेशोत्सव विभिन्न उत्सवों और समारोहों के साथ शुरू हो रहा है। मनपा को कृत्रिम तालाब का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू करना चाहिए ताकि विभिन्न मंडलों को आवश्यक अनुमतियाँ, सुरक्षा और गणपति विसर्जन भक्तिभाव से हो सके। उन्होंने इसके लिए मनपा के प्रत्येक अंचल के लिए एकल-खिड़की योजना शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, जिला परिषद, मनपा, जिला पुलिस अधीक्षक, एनएमआरडीए, पुलिस आयुक्त सभी मिलकर इस गणेशोत्सव के लिए और अधिक व्यवस्थित योजना बनाएँ।

गणेशोत्सव के दौरान लोकल, मेट्रो सेवाएं देर रात तक जारी रहें - लोढ़ा

मुंबई – महाराष्ट्र और मुंबई एमएमआर क्षेत्र में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी उत्सव विश्व प्रसिद्ध है और गणेश भक्त देर रात तक दर्शन के लिए आते हैं। इस समय, गणेश भक्तों के लिए लोकल और मेट्रो ट्रेनें देर रात तक चालू रखने के संबंध में रेलवे और मेट्रो प्रशासन से संपर्क किया जाएगा, ऐसा कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर के संयुक्त पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा। वे ग्रांट रोड स्थित मनपा के डी डिवीजन कार्यालय में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

गणेशोत्सव के दौरान, पूरे महाराष्ट्र से गणेश भक्त मुंबई क्षेत्र में आते हैं। इस समय भक्तों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन का चालू रहना बेहद ज़रूरी है। मंत्री लोढ़ा ने जनता दरबार में यह भी बताया कि इस संबंध में रेलवे और मेट्रो प्रशासन से पत्राचार चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को निर्देश दिया था कि प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया जाए और

लोगों तक सीधे पहुँचा जाए। उनकी समस्याओं को जाना जाए। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि इसी के अनुरूप यह जनता दरबार आयोजित किया गया था। पिछले महीने दक्षिण मुंबई में आयोजित पाँच जनता दरबारों में लगभग दो हज़ार नागरिकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। नागरिकों की नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए म्हाडा, झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण, मनपा और रेलवे सहित बारह विभागों के अधिकारियों को एक ही छत के नीचे लाया गया। इससे नागरिकों की समस्याओं का बिना किसी परेशानी के मौके पर ही समाधान संभव हो पाया है, ऐसा मंत्री लोढ़ा ने बताया। निवासियों को अपने घर खाली करने का नोटिस तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वहां निकासी शिविर स्थापित न हो जाए।

जनता दरबार में म्हाडा से जुड़े पुनर्विकास, मरम्मत और ट्रांज़िशन कैंपों को लेकर कई नागरिकों ने शिकायतें कीं। कई बार नागरिकों को ट्रांज़िशन कैंप दिए बिना ही इमारतें खाली करने के लिए C2 नोटिस थमा दिए गए। मंत्री लोढ़ा ने इन चिंतित निवासियों का पक्ष सुना। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ संजीव जायसवाल के साथ एक बैठक होगी और वे निवासियों को निर्देश देंगे कि जब तक ट्रांज़िशन कैंप तैयार न हो जाए, तब तक उन्हें घर खाली करने का नोटिस न दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ट्रांज़िशन कैंप तैयार नहीं है, तो इमारत की तुरंत मरम्मत की जाए और नागरिकों को राहत दी जाए।

मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीडन, बालश्रम एवं भ्रष्ट्राचार पर केंद्रीत हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र

CC MM YY KK

संपादक की कलम से

अमेरिका का पाक समर्थन

भारतीय सेना ने 1971 के एक पुराने अखबार कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस कटिंग के जरिए यह बताया गया है कि कैसे अमेरिका दशकों से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। ट्रंप के बिगड़े तेवर और बयानबाजी के बीच भारतीय सेना ने अमेरिका को आईना दिखाया है। भारतीय सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 54 साल पुरानी घटना याद दिलाई है। भारतीय सेना ने मंगलवार को 1971 में प्रकाशित एक अखबार की कटिंग शेयर कर अमेरिका पर तंज कसा है। इस कटिंग में दिखाया गया है कि अमेरिका कैसे दशकों से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। भारतीय सेना की यह पोस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर भारतीय सामानों पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वह भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है लेकिन अमेरिका खुद भूल गया कि उसका अतीत कैसा रहा है।

मिलिंद दहिवले
संपादक

फसलों को कीड़ों और कीटों से बचाना भरपूर फसल की गारंटी

राज्य और नागपुर संभाग में संतोषजनक बारिश हुई है और बुवाई भी पूरी हो चुकी है। अब फसलें खेतों में खड़ी हैं। किसानों को उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। अगस्त महीने में फसलों की वृद्धि के साथ-साथ, किसानों को कीटों और इल्लियों के प्रसार को रोकने की योजना भी बनानी होगी। यह विशेष लेख कपास की फसलों पर फूल छेदक और गुलाबी सुंडी के खतरे के साथ-साथ सोयाबीन, तुअर और कपास की फसलों पर दिखाई देने वाले हुमानी इल्लियों के खतरे से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा दी गई सलाह पर आधारित है। जुलाई के दूसरे सप्ताह से कपास की फसलों पर दिखाई देने वाले फूल छेदक कीटों और उसी महीने के अंतिम सप्ताह व अगस्त के प्रथम सप्ताह से गुलाबी सुंडी के प्रकोप से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृषि विभाग ने किसानों को एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत रसचूसक कीटों और गुलाबी सुंडी के प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया है। साथ ही, कृषि विभाग ने सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को बहुभक्षी सुंडी (होलोट्रीचिया प्रजाति) से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कीट प्रबंधन की सलाह दी है।

कपास की फसल की शुरुआती अवस्था में, एफिड्स, टिड्डियों और फूल कीटों का संक्रमण मुख्य रूप से देखा जाता है। शुष्क भूमि कपास की फसल में, एफिड्स का संक्रमण जुलाई के दूसरे सप्ताह से देखा जाता है, जबकि टिड्डियों का जुलाई के अंतिम सप्ताह से और फूल कीटों का अगस्त के पहले सप्ताह से दिखाई देता है। गुलाबी सुंडी का संक्रमण अगस्त के महीने में प्यूपा के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, हुमानी कृमि (होलोट्रीचिया प्रजाति) एक बहुभक्षी कीट है और महाराष्ट्र में, होलोट्रीचिया सेरेंटा प्रजाति मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास और अरहर

की फसलों को नुकसान पहुँचाती है। किसानों को इन सभी प्रकार के कीटों के प्रबंधन के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत बीटी कपास पर कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से कपास चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए। समय-समय पर संक्रमित शाखाओं, पत्तियों और अन्य पर्णसमूह को इकट्ठा करें और उन्हें कीटों के साथ नष्ट कर दें। कपास कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को पोषित करने के लिए लोबिया के साथ अंतरफसल करें। समय पर अंतरफसल लगाकर फसल को खरपतवार मुक्त रखें। उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर अपनाई जानी चाहिए और नाइट्रोजन उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही, यदि एफिड्स, थ्रिप्स और थ्रिप्स की संयुक्त औसत संख्या अधिक पाई जाती है, तो नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए बुप्रोफेजिन 25 प्रतिशत प्रवाह दर 20 मिली. या फिप्रोनिल 5 प्रतिशत प्रवाह दर 30 मिली. या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत 2.5 मिली.

कपास की फसल में गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के लिए, अंकुरण के 40 से 45 दिन बाद फेरोमोन (सुगंध) जाल का उपयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ दो फेरोमोन (सुगंध) जाल या प्रति हेक्टेयर पाँच फेरोमोन (सुगंध) जाल लगाने चाहिए। यदि इन जालों में लगातार तीन दिनों तक आठ से दस पतंगे दिखाई दें, तो गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही, बड़े पैमाने पर जाल लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 सुगंधित जाल लगाने चाहिए। फसल में लार्वा की नियमित रूप से खोज की जानी चाहिए और उन लार्वा को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। फसल के अंकुरण के 35 से 40 दिन बाद हर 15 दिन में 5 प्रतिशत नीम अर्क या एजाडिरेक्टिन 300 पीपीएम 50 मिली प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। यदि गुलाबी सुंडी का प्रकोप 5 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है, तो निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसी एक का छिड़काव करें: क्विनोल्फोस 25 प्रतिशत मिलीलीटर या क्लोरपाइरीफोस 20 प्रतिशत तरल 25 मिलीलीटर या प्रोफेफोस 50 प्रतिशत 30 मिलीलीटर या इंडोक्साकार्ब 15.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 प्रतिशत 10 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

गोलकृमि संक्रमण से सुरक्षा - सोयाबीन, कपास और अरहर की फसलों को बहुभक्षी मिलीबग (होलोट्रीचिया प्रजाति) से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, कीटनाशक का पहला छिड़काव बबूल, नीम और बोरेक्स जैसे पेड़ों पर उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहाँ यह कीट लगातार मौजूद रहता है। कीटनाशकों का प्रयोग करते समय श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो पहले छिड़काव के 3 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। हुमानी इल्ली बारिश के बाद मिट्टी में अंडे देती है। ये इल्लियाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, गन्ना, मिर्च, मूंग, कुसुम, बैंगन, कपास और सूरजमुखी जैसी फसलों की जड़ों को नष्ट कर देती हैं। इससे फसलें उखड़कर ज़मीन पर गिर जाती हैं। यदि इस कीट का प्रकोप कुछ ही स्थानों पर हो, तो जैविक मित्र कवक मेटाराइज़ियम को 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल की जड़ों में डालना चाहिए या मेटाराइज़ियम को 1 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़कना चाहिए। मित्र कवकों का प्रयोग करते समय नमी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण संक्रमण की स्थिति में, प्रबंधन के लिए, कृषि विभाग ने बहुमूल्य सलाह दी है कि फिप्रोनिल 40 प्रतिशत इमिडाक्लोप्रिड 40 प्रतिशत दानेदार 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी को तने के पास डालना चाहिए या कार्बोफ्यूरॉन 3 प्रतिशत दानेदार 33.30 किलोग्राम या थायोमेथोक्सम 0.4 प्रतिशत बिफेन्थ्रिन 0.8 प्रतिशत दानेदार 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या थायोमेथोक्सम 0.9 प्रतिशत फिप्रोनिल 2 प्रतिशत दानेदार 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को तने के पास मिट्टी में तब मिलाना चाहिए जब मिट्टी नम हो।

कृषि विभाग सदैव किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से किसानों को सही समय पर सही सलाह देकर फसल को नुकसान से बचाने और भरपूर फसल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इसका सख्ती से पालन करके किसान भरपूर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और खुश व संतुष्ट भी रह सकते हैं। इसलिए, किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अपनी फसलों की देखभाल करें।

संकलन एवं संपादन
-रितेश एम.डी. भुयार
सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क, नागपुर

बीडीडी चॉल निवासियों को जल्द ही फ्लैट आवंटित

मुंबई - बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को शुरू करने के बाद, उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वर्षों तक जारी रखने के बजाय, शुरू होने के तीन साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है।

मुख्यमंत्री ने सीएम वारू में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण सिंह परदेशी, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वारूम की आज की तीसरी बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने 30 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। पिछली दो बैठकों में कुल 33 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। उस समय लगभग 135 मुद्दों पर चर्चा हुई थी और निर्णय लिए गए थे। इस दौरान इन निर्णयों के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारे पास नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। इसलिए, परियोजनाओं को कम समय में पूरा किया जाना चाहिए। मुंबई सहित राज्य की सभी मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का समय रहते समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, मेट्रो परियोजना के अंतिम स्टेशन के पास आवासीय परियोजनाएँ बनाई जानी चाहिए। मेट्रो परियोजना समय पर पूरी हो, इसके लिए एक कुशल तंत्र बनाना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजना के साथ-साथ अन्य सुविधा परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों के तत्काल वितरण हेतु कार्रवाई करने निर्देश दिए।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में, सभी को परियोजना के समय पर पूरा होने पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के लिए अलग डैशबोर्ड रखने के बजाय, प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति केवल सीएम डैशबोर्ड पर ही दर्ज की जानी चाहिए। परियोजना से संबंधित सभी मामलों को समय-समय पर इस डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाना चाहिए, और परियोजना में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु वॉररूम समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए, कैबिनेट बैठक में विषयों को लाया जाना चाहिए और उन विषयों को पूरा किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में निर्णय के बाद भी यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना वॉर रूम को दी जाए ताकि उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वॉर रूम में लिए गए प्रोजेक्ट और निर्णयों का गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए। यह भी बताया गया कि वर्ली स्थित बीडीडी चॉल के निवासियों को जल्द ही फ्लैट आवंटित किए जाएँगे। साथ ही, यह भी बताया गया कि नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग चॉल के निवासियों को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस समय, बीडीडी चॉल, मुंबई मेट्रो लाइन 4 (वडाला से कासारवडावली), मुंबई मेट्रो लाइन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोली), मेट्रो लाइन 2 बी (डीएन नगर से मंडला), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाइन 9 (दहिसर (पूर्व) से मीरा भयंदर), ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना, बोरीवली से ठाणे लिंक सुरंग परियोजना, उत्तान-विरार सी लिंक, सेवरी-वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर, पुणे मेट्रो, दहिसर से भयंदर लिंक रोड, गोरेगांव मगाठाणे डीपी रोड, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड और नॉर्थ कोस्टल रोड, विरार अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर, धारावी पुनर्विकास परियोजना, जालना नांदेड़ राजमार्ग, पुणे रिंग रोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपति संभाजी नगर परियोजनाएँ जैसे शहर इस दौरान जल आपूर्ति परियोजना, कुदुस आरे कनेक्टिविटी, कुदुस बभलेश्वर विद्युत कनेक्शन परियोजना, शिक्रापुर बभलेश्वर विद्युत परियोजना, वधन बंदरगाह परियोजना आदि की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वॉररूम परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।

जनता को सुशासन का आभास हो, इसके लिए नीतिगत बदलाव जल्द - मुख्यमंत्री

नागपुर - कई लोगों का मानना था कि प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि जनता को सुशासन का आभास हो। इसी को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल के पहले सप्ताह में हमने राज्य स्तर पर सभी ज़िला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया और छह समितियों का गठन किया। इन समितियों ने बहुत ही कम समय में आवश्यक बदलाव किए और व्यावहारिक सिफ़ारिशें कीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मानना था कि इन सिफ़ारिशों के अनुसार तुरंत सरकारी फ़ैसले जारी करने से जनता को सुशासन की भावना का आभास होगा। वे नागपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईएएम) में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के अध्यक्षीय मार्गदर्शन में बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खड़गे, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी, सभी संभागीय आयुक्त और गणमान्य उपस्थित थे।

हमने प्रत्येक संभागीय आयुक्त के अधीन छह समितियाँ गठित की हैं क्योंकि हमारा मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए निजी संस्थानों से रिपोर्ट माँगने के बजाय व्यवस्था का पुनर्गठन और दिन-रात काम करने वाले और जनता के साथ रहने वाले अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादा ज़रूरी होगी। इसमें सभी आयुक्तों और उनके सदस्यों ने राजस्व प्रशासन में सुधार, उन जिलों में कार्य-पद्धतियों का समेकन, जहाँ पूरे राज्य के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों और नियोजन के साथ कार्य किया गया है, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन, विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य में सामंजस्य, जिला स्तर पर विभिन्न समितियों की आवश्यकताओं की जाँच और पुरानी समितियों को समाप्त करने, तथा जिला योजना समिति की कार्य-पद्धतियों के संबंध में अत्यंत कठोर और व्यावहारिक सिफारिशें की हैं। समितियों ने बिना किसी पारिश्रमिक के यह कार्य किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी संभागीय आयुक्तों और उनकी टीमों की प्रशंसा की। सरकार को विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से कई सिफारिशें प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्हें कैसे लागू किया जाए, यह प्रश्न बना रहता है। इन समितियों ने यह प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यह अधिक संतोषजनक है कि इन सिफारिशों को सरकारी निर्णय प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया है।

सरकार जिला योजना समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है। इस व्यय और इससे प्राप्त परिणामों पर विचार करने की आवश्यकता है। हाल के दिनों में, जिला वार्षिक योजना को रोजगार के साधन के रूप में भी देखा गया। यह चिंता का विषय था। उद्देश्य यह है कि कोई भी जिला वार्षिक योजना रोज़गार का साधन न बने, बल्कि उससे बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित हों। इसके लिए सुधार ज़रूरी थे। समिति ने इस बात का अध्ययन किया कि किन योजनाओं को स्वीकार किया जाए और किनको बाहर रखा जाए। यह उचित नहीं था कि ज़िला कलेक्टर इस समिति के सदस्य सचिव का पद संभालें और उनके पास कोई अधिकार न हों। समिति ने इसकी गहन जाँच की है और ज़िला कलेक्टर को ज़िला योजना समिति के कुल प्रावधान का पाँच प्रतिशत ज़िले की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आरक्षित करने की सिफ़ारिश की है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

हमने एक विकसित महाराष्ट्र का विज़न रखा है। इसके लिए हमने शुरुआत में 100 दिन और बाद में 150 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया। नीति आयोग ने इस संबंध में हमारी योजना की सराहना की। हमने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए, यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के सामने प्रशासन की कोई बाधा न आए, उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा मिले और सरकारी स्तर पर उनका काम तेज़ी से हो। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने व्यापारियों को अच्छी सेवाएँ प्रदान करें, तो हम अमेरिका द्वारा लगाए गए पच्चीस प्रतिशत कर की चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं। आज भी, प्रशासन में कई चुनौतियाँ हल नहीं हुई हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के कारण कई पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं ताकि हम लगभग 70,000 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भर सकें। हमें इस संबंध में लंबित मुद्दों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अगले 150 दिनों में अनुकंपा का एक भी पद खाली न रहे।

फडणवीस ने हमें 2029 तक राजस्व विभाग की प्रगति का एक विजन दिया है, और राजस्व मंत्री चंद्रकर बावनकुले ने आज विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में, हम उनके दिखाए गए विजन पर काम करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि राजस्व विभाग देश में नंबर एक होगा। बावनकुले आज नागपुर में आयोजित राजस्व सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास खड़गे, नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा सहित राज्य के सभी विभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर उपस्थित हैं।

बावनकुले ने महाराष्ट्र में राजस्व विभाग के समक्ष चुनौतियों, विभिन्न राजस्व सुधारों और भविष्य की दिशा पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अप्रैल में पुणे में आयोजित राजस्व सम्मेलन में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजस्व विभाग के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के छह संभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता में छह समितियों का गठन करने के निर्देश दिए थे। सम्मेलन के पहले दिन इन समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। बावनकुले ने इन रिपोर्टों में दिए गए सुझावों और सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छह राजस्व आयुक्तों और जिला कलेक्टरों से आमने-सामने बातचीत की और राजस्व विभाग में सुधारों को जनोन्मुखी बनाने पर चर्चा की।

बावनकुले ने कहा कि सरकार छह संभागीय आयुक्तों की समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर जीआर जारी करके लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। बावनकुले ने भविष्य में कई पुराने कानूनों और जटिल नियमों को हटाने की बात कहते हुए कहा कि जनता को मंत्रालय तक पहुँचने में होने वाली परेशानी और खर्च से बचने के लिए, हम मंत्रियों के अधिकारियों का विकेंद्रीकरण करेंगे और उन्हें संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि रेत की अनुपलब्धता के कारण कुछ जगहों पर जनता में रोष है, हम इस रोष को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रेत को लेकर एक बहुत अच्छी नीति लेकर आई है। अब इसे लागू करना सभी राजस्व अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है। सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता को किसी भी हालत में परेशानी न हो। सरकार ने छात्रों, किसानों, खेतिहर मजदूरों और परिवारों सहित समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं। नीतियाँ तैयार कर ली गई हैं। उम्मीद है कि भविष्य में इनके क्रियान्वयन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने महीने में चार दिन महाराष्ट्र के हर जिले और तहसील कार्यालय का दौरा करने का फैसला किया है। इसी प्रकार, राजस्व मंत्री ने अपेक्षा व्यक्त की कि संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और तहसीलदार प्रत्येक शुक्रवार को अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता से संवाद स्थापित करें। प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में निवासी उप जिला कलेक्टर का पद होता है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्य विभाजन को देखते हुए यह दायित्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया जाएगा।

बावनकुले ने यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से अनुशंसा कर रहे हैं कि अकृषक से सनद शब्द हटा दिया जाए। बेहद मामूली मामलों पर अदालती मुकदमों की संख्या कम की जाए। राजस्व मंत्री के पास आने वाले बेहद मामूली मामलों पर अदालती मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताते हुए, राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि ऐसी पहल करने की आवश्यकता है जिससे वर्षों से चले आ रहे सड़क विवाद दो चरणों में समाप्त हो सकें और राजस्व विभाग ऐसी योजना बनाए। राजस्व अधिकारियों, विशेषकर संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों का कार्य समय मंत्रियों के प्रोटोकॉल को बनाए रखने में व्यतीत हो रहा है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि अब से संभागीय आयुक्तों या जिला कलेक्टरों को अपने प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए नहीं आना चाहिए और इस समय का उपयोग जनता के कामों के लिए करना चाहिए। इस अवसर पर, आकांक्षा जिला एवं तालुका अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईटः www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

CC MM YY KK

CC MM YY KK

न्यूज गैलरी

अजीत डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात

मास्को – भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं। डोभाल का यह रूस दौरा पहले से प्रस्तावित था। ट्रंप की ओर से रूस के साथ भारत के संबंधों पर दिए गए बयानों के बाद डोभाल का यह दौरा बेहद अहम हो गया है। तेल आयात को लेकर अमेरिका की ओर से भारत को धमकी दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस और भारत के बीच संबंधों को मजबूती देने के मकसद से मॉस्को पहुंचे हैं। हालांकि, डोभाल की यह यात्रा पहले से तय थी, लेकिन अब ट्रंप की ओर से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों के कारण इसकी और भी ज्यादा अहमियत हो गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान अन्य रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर वार्ता भी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। डोभाल के मॉस्को दौरे को लेकर रूस ने भारत के पक्ष में बयान जारी किया है। क्रेमलिन ने अमेरिका पर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अनुचित दवाब डालने का आरोप लगाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि हमने कुछ बयान सुने हैं जो वास्तव में धमकी की तरह हैं। इनमें देशों पर दवाब डाला जा रहा है कि वह रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लें। हम ऐसे बयानों को वैधानिक नहीं मानते हैं। इस बीच रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने देश के उप रक्षा मंत्री कर्नल-जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की है। मुलाकात को दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारतीय दूत ने कर्नल-जनरल फोमिन से मुलाकात की, जो अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग के प्रभारी हैं।

लाइव प्रसारण से पहले महिला रिपोर्टर का मोबाइल लेकर भागा

ब्राजील – एक टीवी रिपोर्टर के साथ लूट की घटना हुई है। लूट की घटना उस वक्त हुई जब लाइव प्रसारण शुरू होने वाला था। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला टीवी रिपोर्टर के साथ लाइव प्रसारण शुरू होने से कुछ ही सेकंड पहले हैरान करने वाली घटना घटी है। महिला रिपोर्टर लाइव टीवी पर आने ही वाली थी कि एक चोर ने उसका फोन छीनने की कोशिश की। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कैमरे में कैद यह घटना ब्राजील के मशहूर शहर रियो डी जनेरियो की सड़कों पर हुई है। ब्राजीलियाई नेटवर्क बैंड रियो की रिपोर्टर क्लारा नेरी पिछले हफ्ते रियो डी जेनेरियो की सड़कों से लाइव प्रसारण की तैयारी कर रही थीं, तभी यह चौंकाने वाली घटना घटी। वीडियो में दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स पीछे से आता है और रिपोर्टर के पास से गुजरते हुए उसके हाथ से उसका फोन छीन लेता है। यह सब तब होता है जब कैमरा ऑन रहता है। हालांकि, चोर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाता है। अच्छी बात यह रही कि भागते समय चोर के हाथ से फोन गिर गया, जिसे क्लारा ने उठा लिया। इस घटना के बाद क्लारा नेरी ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "लाइव जाने से पहले यह एक बहुत डरावना अनुभव था, लेकिन जरूरी बात यह है कि मैं ठीक हूं और सबकुछ ठीक हो गया।" नेरी ने सोशल मीडिया पर उनका साथ देने वालों को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, "मेरे सहकर्मियों, सैन्य पुलिस और सिविल पुलिस के संदेशों और समर्थन के लिए धन्यवाद।" उन्होंने संदिग्ध की पहचान करने में जनता से भी मदद की अपील की और लिखा "चलो उसका चेहरा साझा करते हैं, वह पहचाना जाना चाहता है।"

भारतीय कैब ड्राइवर पर हुआ हमला; कहा 'अपने देश वापस जाओ'

लंदन – आयरलैंड में एक बार फिर भारतीय मूल के शख्स पर हम हुआ है। भारतीय मूल के शख्स का नाम लखवीर सिंह है। लखवीर सिंह कैब ड्राइवर हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आयरलैंड में 23 वर्षों से रह रहे भारतीय मूल के एक टैक्सी चालक पर राजधानी डबलिन में बिना किसी उकसावे के हमला किया गया है। हमलावरों ने चिल्लाते हुए पीड़ित से कहा कि 'अपने देश वापस जाओ।' स्थानीय पुलिस ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित लखवीर सिंह (40) ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने शुक्रवार की रात 20 वर्ष की आयु के दो युवकों को टैक्सी में बैठाया और डबलिन के बैलीमन उपनगर स्थित पॉपिनट्री छोड़ दिया। सिंह के मुताबिक, गंतव्य पर पहुंचने के बाद दोनों युवकों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उनके सिर पर एक बोतल से दो बार वार किया। उन्होंने बताया कि संदिग्धों ने भागते समय चिल्लाते हुए कहा, 'अपने देश वापस जाओ।'

लखवीर सिंह ने 'डबलिन लाइव' से कहा, ''पिछले 10 वर्षों में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मैं अब बहुत डरा हुआ हूं और इस वक्त टैक्सी चलाना छोड़ दिया है। दोबारा सड़क पर लौटना मुश्किल होगा। मेरे बच्चे भी डरे हुए हैं।'' डबलिन पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सिंह को ब्यूमोंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, उनकी चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं ऋऋहैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, ''एक अगस्त 2025 की रात करीब 11:45 बजे बैलीमन स्थित पॉपिनट्री में एक टैक्सी चालक पर हमले की सूचना मिली, जिसकी जांच जारी है। 40 साल के पीड़ित को इलाज के लिए ब्यूमोंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।''

यह घटना भारतीय दूतावास की ओर से शुक्रवार को जारी उस परामर्श के तुरंत बाद हुई, जिसमें राजधानी डबलिन और उसके आसपास हालिया हमलों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई थी। दूतावास ने कहा था, "हाल के समय में आयरलैंड में भारतीय नागरिकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और विशेषकर अकेले और सुनसान इलाकों में देर रात बाहर ना निकलें।''

इस घटना से पहले 19 जुलाई को डबलिन के टालगट इलाके में 40 वर्षीय एक भारतीय नागरिक पर नस्ली हमला हुआ था। घटना के विरोध में प्रवासी भारतीय समुदाय ने 'स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म' नाम से एक प्रदर्शन भी आयोजित किया था। कृत्रिम मेधा (एआई) विशेषज्ञ डॉ संतोष यादव ने पिछले सप्ताह एक "बर्बर, नस्ली हमले" की जानकारी 'लिंक्डइन' पर साझा की थी। उन्होंने बताया था कि एक दिन जब वह अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, तो छह किशोरों ने उन पर पीछे से हमला किया था। यादव ने कहा, "यह कोई अकेली घटना नहीं है। डबलिन में भारतीयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर नस्ली हमले बढ़ रहे हैं। सरकार चुप है, कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है।''

टालगट साउथ से फाइन गेल पार्टी के काउंसिलर बेबी परेप्पडन ने भी घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ''लोगों को समझना चाहिए कि अधिकतर भारतीय आयरलैंड में कार्य परमिट पर आए हैं और स्वास्थ्य देखभाल या सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। वो देश के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं।''

गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी और नरीमन पॉइंट पर 'पर्यटन सुरक्षा बल'

मुंबई – पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों पर 'सुरक्षा बल' की स्थापना एक अभिनव पहल है। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने निर्देश दिया है कि मुंबई के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए 'गेटवे ऑफ इंडिया', 'गिरगांव चौपाटी' और नरीमन पॉइंट पर 'पर्यटन सुरक्षा बल' की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जाएं। इस संबंध में मंत्री देसाई के सरकारी आवास मेघदूत पर एक बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव अतुल पाटने, पर्यटन निदेशक डॉ. बी.एन. पाटिल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर जायसवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री देसाई ने कहा कि वर्तमान में महाबलेश्वर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 'पर्यटन सुरक्षा बल' की पहल चल रही है। राज्य में इस पहल का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। मुंबई में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक सुरक्षा की दृष्टि से इस निर्णय को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी और नरीमन पॉइंट पर 'पर्यटन सुरक्षा बल' की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्री देसाई ने इस अवसर पर निर्देश दिए कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की नियुक्ति हेतु तत्काल कार्रवाई करे।

अलमट्टी और हिप्पार्गी बांध में अनियमितताओं की जांच राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा

नई दिल्ली – कर्नाटक में अलमट्टी बांध और हिप्पार्गी बांध के निर्माण में अनियमितताओं की जांच राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात के बाद मीडिया को यह जानकारी दी गई। श्रमशक्ति भवन में आज हुई बैठक में राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री विखे पाटिल, कोल्हापुर के पालक मंत्री प्रकाश अबितकर और सह पालक मंत्री माधुरी मिसाल के साथ कोल्हापुर और सांगली जिलों के सांसद और विधायक प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। बैठक में केंद्रीय जल बोर्ड आयोग के अध्यक्ष, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की प्रधान सचिव देबाश्री मुखर्जी उपस्थित थीं।

कर्नाटक सरकार ने अलमट्टी बांध के पूर्ण संग्रहण स्तर (एफआरएल) को 519.60 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन बांध की मौजूदा ऊँचाई के कारण, 2019 और 2021 में हुई भारी वर्षा से इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। अगर भविष्य में भारी वर्षा होती है, तो इस बांध का बैकवाटर और अधिक नुकसान पहुँचा सकता है। भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए राज्य के जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को कर्नाटक सरकार द्वारा अलमट्टी धारन के विरुद्ध की गई अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया।

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए अध्ययन के अनुसार, अलमट्टी बांध के कारण कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नदी की वहन क्षमता प्रभावित हुई है। सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ के पानी की निकासी की गति कम हो गई है। इससे निकटवर्ती कोल्हापुर और सांगली जिलों में स्थायी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता बिगड़ गई है। इसका कृषि के साथ-साथ शहरी जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्रतिनिधिमंडल की ओर से मांग की गई कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बैठक में प्रतिनिधिमंडल में माननीय सांसद शाहू शाहजी छत्रपति, विशाल पाटिल, धैर्यशील माने, धनंजय महाडिक, माननीय विधायक सतेज पाटिल, अरुण लाड, डॉ. विश्वजीत कदम, राहुल अवाडे, राजेंद्र पाटिल येद्रवकर, आदि शामिल थे।

फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार

नई दिल्ली – सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के माध्यम से "नियमों का अनुपालन न करने वाले फास्टैग' का पता लगाकर और उन्हें काली सूची में डालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को समयबद्ध रूप से मजबूत किया है। आईएचएमसीएल के 19 अगस्त, 2019 के नीति परिपत्र के अनुसार, शुल्क प्लाज़ा संचालकों को ऐसे उल्लंघनों की सूचना संबंधित अधिग्रहणकर्ता बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देनी होगी। बैंकों को ऐसे मामले की पुष्टि करनी होगी और गैर-अनुपालन वाले फास्टैग को काली सूची में डालना होगा, जबकि आईएचएमसीएल अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके बाद, 16 जुलाई, 2024 के परिपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों को दोहराया गया, जिसके अनुसार जिन वाहनों पर वैध फास्टैग नहीं लगे हैं, उनसे लागू शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा। परिपत्र में इसी प्रावधान को आधार बनाकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगे हैं, वे भी इसी श्रेणी में आएंगे और उन्हें लागू दर का दोगुना शुल्क नकद में देना होगा जिससे रोकथाम लागू होगी। इन आदेशों को सुव्यवस्थित करने के लिए, 26 जून, 2025 के परिपत्र में एक रिपोर्टिंग प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुल्क संग्रह एजेंसियों को etc.operations@ihmcl.com पर साप्ताहिक डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक था। इन रिपोर्टों के आधार

पर, आईएचएमसीएल ने एनपीसीआई को ब्लैकलिस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया। शुल्क संग्रह करने वाली सभी एजेंसियों और को समय-समय पर फास्टैग के सही तरीके से नहीं चिपके होने ' या फास्टैग हाथ में रखने यानी टैग-इन-हैंड' के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए हितधारकों के साथ जुड़ रही है। इस संबंध में 25 जून, 2025 को एक फिनटेक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बैंकों, फिनटेक, एनपीसीआई, भुगतान सेवा प्रदाताओं और टोलिंग प्रणाली संचालकों सहित हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि फास्टैग के उपयोग के मामलों के विस्तार और विभिन्न सेवाओं में फास्टैग की अंतर-संचालनीयता पर विचार-विमर्श किया जा सके। कार्यशाला में चर्चा का मुख्य उद्देश्य ईंधन भुगतान, ईवी चार्जिंग, पार्किंग, भीड़भाड़ वाले टोल आदि जैसे क्षेत्रों में फास्टैग की उपयोगिता को व्यापक बनाना था। मूल्यवर्धित सेवाओं के एकीकरण, गतिशीलता के लिए डेटा-संचालित समाधान और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल सुविधाओं पर चर्चा की गई। ताकि फास्टैग को एक एकीकृत डिजिटल गतिशीलता मंच के रूप में स्थापित किया जा सके, जिसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।

न्यूजीलैंड में सूटकेस में जिंदा मिली 2 साल की बच्ची; महिला गिरफ्तार

वेलिंगटन – एक बच्ची सूटकेस में मिली है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सूटकेस में 2 साल की बच्ची के जिंदा मिलने के बाद एक महिला को बाल उपेक्षा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि बस के चालक ने सामान रखने वाले स्थान में रखे एक सूटकेस में बच्ची को पाया था। 'डिटेक्टिव इंस्पेक्टर' साइमन हैरिसन ने एक बयान में कहा कि ऑकलैंड के उत्तर में काईवाका बस्ती में एक बस स्टॉप पर जब एक यात्री ने चालक से उसका सामान निकालने के लिए कहा तो उसने बैग के अंदर हलचल देखी। हैरिसन ने बताया कि जब चालक ने सूटकेस खोला तो उसमें 2 साल की बच्ची थी और उसका शरीर तप रहा था, हालांकि उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी।

भूख से शरीर बन चुका कंकाल बंधक को अपनी ही कब्र खोदने को किया मजबूर

गाजा – हमास आतंकियों द्वारा एक इजरायली बंधक से सुरंग में अपनी ही कब्र खोदने के लिए मजबूर करते दिखाया गया है। इजरायली बंधक कई दिनों से भूखा दिख रहा है, जिससे उसका शरीर भी कंकाल हो चुका है। हमास के आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक इजरायली बंधक को कैमरे के सामने उससे उपनी ही कब्र खोदनेके लिए मजबूर कर दिया। इस सनसनीखेज वीडियो को देखने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। इस वीडियो को इजरायल सरकार के एक पूर्व प्रवक्ता ने अपने एक्स एकाउंट पर शेयर किया है।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को कहा- मैं आपकी जगह PM मोदी को करूंगा कॉल

ब्राजील – ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे बल्कि पीएम मोदी को कॉल करेंगे। अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर खींचतान जारी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि लूला उनसे कभी भी टैरिफ के मुद्दो पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को कहा था कि वो कभी भी कॉल करके टैरिफ पर चर्चा

कर सकते हैं। इस पर राष्ट्रपति लूला ने कहा कि इससे अच्छा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ब्राजील अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों का उपयोग करेगा।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि उनकी सरकार ब्रिक्स भागीदारों सहित अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को मजबूत करने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है। ब्रासीलिया में एक कार्यक्रम में बोलते हुए लूला ने कहा, "2025 में, हम अपने हितों की रक्षा के लिए WTO से लेकर सभी संभावित उपायों का सहारा लेंगे।" ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, रिपब्लिकन पार्टी की भारतवंशी नेता निक्की हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी है। हेली ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चीन, जो हमारा एक विरोधी है और रूसी व ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई है। चीन को छूट ना दें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब ना करें।"

हमास ने बंधकों को भूखा रखा, इजरायल ने कहा- आतंकी खा रहे हैं मांस, मछली

इजरायल – इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के बीच इजरायल ने कहा है कि हमास बंधकों को भूखा रख रहा है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि आतंकवादी दावत उड़ा रहे हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में बंधकों को रिहा किए जाने की मांग की है। इजरायल ने बंधकों की हालत को देखते हुए यह बैठक बुलाई थी। दरअसल, हाल में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एव्यातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। बंधक का यह वीडियो सामने आने के बाद इजरायल भड़क गया है। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 100 से अधिक लोगों की भुखमरी के कारण मौत हो गई है जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। गाजा में इजरायल के हमले जारी हैं।

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने परिषद के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ही

अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर 'झूठ फैलाने' का आरोप लगाया। वह परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क आए हैं। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल में हुए हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा गया, जबकि 'आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं।' सार ने दावा किया कि इजरायल, गाजा में 'भारी मात्रा में सहायता सामग्री' पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास खाद्य सामग्री को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है।

इजरायल के शीर्ष राजनयिक ने यह भी आरोप लगाया कि हमास, इजरायल के साथ युद्ध जारी रखना चाहता है, ना कि युद्धविराम के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई का समर्थन किया। उन्होंने दुष्प्रचार के उद्देश्य से बंधकों की परेड कराने की निंदा करते हुए इसे 'घृणित' कृत्य बताया। कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डोरोथी शीया ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि गाजा में भुखमरी है और अमेरिका नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 24 वर्षीय एव्यातर डेविड के ''व्यथित करने वाले वीडियो'' पर कहा, ''हम किसी के भी साथ, विशेषकर बंधक बनाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को अस्वीकार करते हैं।'' साथ ही उन्होंने कहा, ''इजरायल दुनिया से भुखमरी के खिलाफ खड़ा होने की मांग कर रहा है जबकि वास्तव में वह एक बड़ी आबादी को भूखा मार रहा है।''

न्यूज गैलरी

'कॉटन टू क्लॉथ' के माध्यम से व्यापार बढ़ाने का अवसर - रावल

मुंबई – महाराष्ट्र और दक्षिण कोरिया के बीच कपड़ा क्षेत्र में व्यापार वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं। प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जयकुमार रावल ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के कपास और दक्षिण कोरिया की कपड़ा मशीनरी के बीच साझेदारी से आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। दक्षिण कोरियाई महावाणिज्य दूत डोंगवान यू ने सह्याद्री अतिथि गृह में मंत्री रावल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महाराष्ट्र और कोरिया के बीच व्यापार वृद्धि के विभिन्न अवसरों पर चर्चा हुई। रावल ने कहा, "महाराष्ट्र भारत का पावरहाउस है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और महाराष्ट्र तथा कोरिया के बीच व्यापार वृद्धि के अवसरों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। चूँकि महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति उपलब्ध है, इसलिए महाराष्ट्र और कोरिया में विभिन्न निवेश और व्यापार अवसरों पर विचार करके इच्छुक पक्षों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।" मंत्री रावल ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापारिक साझेदारी, विशेष रूप से महाराष्ट्र से कपास और कोरिया से वस्त्र मशीनरी के माध्यम से, आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे समेत विभिन्न जिलों में उद्यमियों को सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर मंत्री रावल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कृषि प्रसंस्करण के साथ-साथ फल-सब्जी निर्यात में भी अग्रणी है और कोरियाई उद्यमियों का राज्य में स्वागत किया जाएगा। कोरियाई महावाणिज्य दूत डोंगवान यू ने कहा कि व्यापार और निवेश की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने बताया कि मुंबई-पुणे क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की कई कोरियाई कंपनियाँ मौजूद हैं। उन्होंने मंत्री रावल को 12 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित होने वाले कोरियाई महोत्सव में आमंत्रित किया।

खनिज निष्कर्षण क्षेत्र में महाराष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार

मुंबई – महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय से ही महाराष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि महाराष्ट्र व्यापार वृद्धि के माध्यम से इन संबंधों को और मज़बूत करने का इच्छुक है और खनिज खनन क्षेत्र में व्यापार वृद्धि के अपार अवसर मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका के महावाणिज्य दूत गिदोन लाबाने ने सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल मंत्री रावल से शिष्टाचार भेंट की। दोनों ने व्यापार वृद्धि के क्षेत्रों पर औपचारिक चर्चा की। मंत्री रावल ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही विकास के पथ पर अग्रसर हैं। महाराष्ट्र भारत का पावरहाउस है। यहाँ पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावनाएँ मौजूद हैं। खनिज निष्कर्षण, विभिन्न उत्पादों आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके महाराष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मंत्री रावल ने कहा कि महाराष्ट्र का दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमेशा से लगाव रहा है। दक्षिण अफ्रीका के महावाणिज्य दूत गिदोन लाबाने ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किए गए कार्यों से प्रेरित होकर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत कृषि उत्पादन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और दक्षिण अफ्रीका को मदद की उम्मीद है।

पहलगाम हमलावरों की रिपोर्ट

पहलगाम हमलावरों की पहचान और पृष्ठभूमि पर एक रिपोर्ट मीडिया/सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से प्रसारित की जा रही है और इसे सेना के हवाले से बताया जा रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों के किसी भी अधिकृत मीडिया हैंडल ने ऐसा कोई दस्तावेज़ तैयार या जारी नहीं किया है और न ही सशस्त्र बलों के जनसंपर्क कार्यालयों/मनोनीत प्रवक्ताओं द्वारा इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है। यह रिपोर्ट खुले स्रोतों से एकत्रित मुठभेड़ के बाद के निष्कर्षों पर आधारित जानकारी का संकलन प्रतीत होती है।

'स्मार्ट' योजना के माध्यम से किसानों की आत्मनिर्भरता

छोटे और सीमांत किसानों और कृषि उद्यमियों को कृषि उत्पादों की समावेशी और प्रतिस्पर्धी मूल्य श्रृंखला विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राज्य में "बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना" लागू की जा रही है। इस परियोजना का लाभ उठाकर, कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। कंचनी कंपनी इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। स्मार्ट योजना के तहत राज्य में शुरू की गई कुल 14 जिनिंग में से, कंचनी राज्य की पहली जिनिंग बन गई। सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए, किसानों ने एक साथ आकर एक किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना की और सीधे फसलों की एक मूल्य श्रृंखला बनाई और कच्चे माल की प्रक्रिया के माध्यम से बिचौलियों के पास जाने वाले पैसे को डायवर्ट किया। किसानों द्वारा किसानों के लिए की गई पहल और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आत्मनिर्भरता को मिला बढ़ावा चंद्रपुर जिले के वरोरा में कंचनी किसान उत्पादक कंपनी है।

यह कंपनी कपास का प्रसंस्करण कर कपास की गांठें सीधे चीन, वियतनाम आदि देशों को निर्यात करती थी। इस परियोजना के लिए, संयुक्त निदेशक कृषि नागपुर कार्यालय द्वारा "बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और

ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना" योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और 3 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। किसानों की एकता और सरकार के मजबूत समर्थन के कारण, कंपनी ने 100 करोड़ का वार्षिक कारोबार हासिल किया है। संभाग के तुमसर, कन्हान और कामठी में अंटांग जैसी किसान उत्पादक कंपनियां भी कंचनी कंपनी के नक्शेकदम पर चलकर तेज गति से आगे बढ़ने लगी हैं।

छोटे किसानों को साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने की समस्या के समाधान के लिए, किसानों ने एकजुट होकर 2017 में कंचनी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का पंजीकरण और स्थापना की। स्मार्ट परियोजना के तहत राज्य सरकार से प्राप्त 5 करोड़ रुपये के अनुदान से कपास ओटाई और प्रेसिंग इकाई स्थापित की गई। 24 डीआर ओटाई और प्रेसिंग इकाई के साथ-साथ सफाई और रीडिंग शेड का निर्माण भी किया गया। इससे किसान अपने कच्चे कपास को संसाधित करके गांठें बना पाए, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक लाभ हुआ। शुरुआत में, इस कंपनी ने सोयाबीन, चना और अरहर जैसी फसलों का व्यापार शुरू किया। वर्ष 2023 में 350 किसानों के लिए 900 कपास की गांठें तैयार की गईं। इस जिनिंग में किसान प्रतिवर्ष लगभग 95 हजार क्विंटल कपास लाते थे और उससे 18.5 हजार गांठें बनाई जाती थीं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1 लाख 80 हजार क्विंटल कृषि उपज का सामूहिक संग्रह किया गया और लगभग 8 हजार किसानों को इस विक्रय प्रणाली का लाभ दिया गया। चना बीज उत्पादन के माध्यम से 250 किसानों को बाजार मूल्य से 1100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मूल्य दिया गया, जो सभी किसानों के विकास की दृष्टि से एक अत्यंत संतोषजनक तस्वीर है।

कंचनी कंपनी किसानों को व्यापारी बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। इस कंपनी के साथ, किसानों को अब दलाली नहीं देनी पड़ती है और उनकी आय में कटौती नहीं होती है। सामूहिक बिक्री प्रणाली बनाकर, किसानों की उपज बाजार में उच्चतम संभव मूल्य पर बेची जाती है। किसानों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, उन्हें बाजार से जोड़ा जा रहा है। 2,000 से अधिक किसान सदस्यों के साथ, इस कंपनी के माध्यम से किसानों को समय पर उनकी कृषि उपज का भुगतान किया जाता है। चंद्रपुर, यवतमाल और गढ़चिरौली जिलों की 52 किसान कंपनियों ने अन्य राज्यों में अरहर, चना, हल्दी, चावल, सोयाबीन और कपास की गांठें बेचने के लिए कंचनी कंपनी के साथ आपसी समझौता किया है। कंपनी उन्हें अच्छे खरीदार ढूंढती है और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं लेती है। वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने यहां बंधक सुविधाएं प्रदान की हैं। कंचनी के साथ ही नागपुर जिले के कामठी तालुका के कन्हान में भी किसान उन्नति का सपना मन में लिए समूह खेती और स्मार्ट परियोजना के तहत विकास के पथ पर अग्रणी बने हैं। 2018 में 20 किसानों ने मिलकर कन्हान एग्रोविजन कंपनी की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने एक चावल मिल शुरू की। सरकार की मदद से प्रगति के पथ पर अग्रसर इस कंपनी को स्मार्ट परियोजना ने एक नई दिशा दी। 2024 में इस परियोजना के तहत 87 लाख रुपये का अनुदान मिला, जिससे गेहूं की सफाई और ग्रेडिंग मशीन, गोदाम, मशीन निर्माण के लिए गेहूं शेड, 60 मीट्रिक टन क्षमता का धर्मका आदि सामग्री खरीदी गई। इसके जरिए भोपाल की आईटीसी कंपनी को भी सामान की आपूर्ति की जा रही है।

अधिकारी सप्ताह में एक बार गांवों का दौरा करें – बावनकुले

नागपुर – जिले के गाँवों में सड़क और पानी की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए, प्रत्येक संबंधित अधिकारी को गाँव का दौरा करना ज़रूरी है। गाँव का दौरा करने से गाँव की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को सप्ताह में एक बार संबंधित गाँव का दौरा करना होगा। राजस्व मंत्री और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज यहाँ कहा कि स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पालकमंत्री ने मौदा तालुका के कोडामेंढी और खाट गाँवों का दौरा किया। वे इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक टेकचंद सावरकर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

समय मिलने पर हम आम लोगों की शिकायतों को समझ रहे हैं। हम आम नागरिकों के विकास कार्यों के अनुकूल निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिक अपने क्षेत्र के लिए किए जा रहे कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, हमने हर हफ्ते गाँव का दौरा करके उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को समझने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर पालकमंत्री श्री बावनकुले ने कहा कि गाँव के दौरे के दौरान सरपंच और लोगों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। सड़कें किसानों के लिए एक गहरा मुद्दा है। अगले पाँच वर्षों में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण करके किसानों के इस गहरे मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। पालकमंत्री श्री बावनकुले ने इस अवसर पर कहा कि आम जनता के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मजबूती से काम चल रहा है।

इस बीच, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और अभ्यावेदनों को स्वीकार किया और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बावनकुले ने मौदा खेल परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक, फुटसल मैदान और व्यायामशाला सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक टेकचंद सावरकर, जिला क्रीड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक, क्रीड़ा अधिकारी माया दुबेले सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

महाराष्ट्र राज्य नाटक प्रतियोगिता' के लिए ऑनलाइन प्रविष्टियाँ 31 तक उपलब्ध

मुंबई – महाराष्ट्र सरकार का सांस्कृतिक कार्य निदेशालय 3 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली शौकिया मराठी, हिंदी, संगीत और संस्कृत राज्य नाट्य प्रतियोगिताओं के साथ-साथ बाल नाट्य प्रतियोगिताओं और दिव्यांगों के लिए बाल नाट्य प्रतियोगिताओं के लिए नाट्य संस्थाओं से ऑनलाइन प्रविष्टियाँ आमंत्रित कर रहा है। सांस्कृतिक कार्य निदेशक विभीषण चावरे ने बताया कि राज्य नाट्य प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार और सांस्कृतिक कार्य विभाग की सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी के मार्गदर्शन में आयोजित की जाएगी। 22वीं महाराष्ट्र राज्य बाल नाटक प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर दिसंबर 2025 से 10 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जबकि 64वीं शौकिया हिंदी, संगीत और संस्कृत नाटक प्रतियोगिता का अंतिम दौर दिसंबर 2025 से एक-एक केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टियाँ पंजीकृत शौकिया नाट्य संस्थाओं के साथ-साथ पिछले वर्ष राज्य नाट्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली नाट्य संस्थाओं के लिए नियम निदेशालय की वेबसाइट https://mahanatyaspardha.com पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगी । प्रविष्टियाँ आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रविष्टियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। यदि प्रविष्टि प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए गए हैं या पूर्ण विवरण नहीं भरा गया है, तो ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र नहीं भरा जा सकेगा। प्रतियोगिता हेतु संस्था के चयन के पश्चात, यदि संस्था सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक केंद्र पर प्रयोग प्रस्तुत नहीं करती है, तो प्रवेश पत्र के साथ जमा की गई राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी। नाट्य प्रतियोगिता हेतु संस्था पर सरकारी नियम बाध्यकारी होंगे।

भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी की पुन: पुष्टि की

आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह का 11वां सत्र आज नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के

ढांचे के अंतर्गत आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष की ओर से सत्र की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने की और रूसी पक्ष की ओर से वहां के उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री श्री एलेक्सी ग्रुजदेव ने की। इस बैठक में दसवें सत्र के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। चर्चाओं में आधुनिकीकरण, खनन, उर्वरक और रेल परिवहन के साथ-साथ सहयोग के उभरते क्षेत्रों पर उप-समूहों द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी शामिल थी। मुख्य फोकस क्षेत्रों में एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग शामिल था, जिसमें एक आधुनिक पवन सुरंग सुविधा की स्थापना, छोटे विमान पिस्टन इंजन का उत्पादन और कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3डी प्रिंटिंग में संयुक्त विकास शामिल है। दोनों पक्षों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी अवसरों का पता लगाया। दोनों पक्षों ने एल्युमीनियम, उर्वरक और रेलवे परिवहन के क्षेत्र में संवर्धित सहभागिता का स्वागत किया, साथ ही खनन क्षेत्र के उपकरण, अन्वेषण और औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन में क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भी स्वागत किया। बैठक का समापन दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा 11वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी और औद्योगिक व आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की गई। इस सत्र में दोनों पक्षों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक - अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली – यूएसबीआरएल परियोजना, आजादी के बाद देश में शुरू की गई सबसे कठिन नई रेल लाइन परियोजनाओं में से एक है। यह भूभाग युवा हिमालय से होकर गुजरता है, जो भूवैज्ञानिक विविधताओं और असंख्य समस्याओं से भरा है। इस परियोजना में रेलवे ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है, इसका आर्च स्पान 467 मीटर है और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इस परियोजना में अंजी खड्ड पर भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टेड पुल बनाया गया है। इसका ब्रिज डेक नदी तल से 331 मीटर ऊंचा है और इसके मुख्य तोरण की ऊंचाई 193 मीटर है। यूएसबीआरएल परियोजना ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान दिया है, इसमें रोज़गार सृजन भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इस परियोजना ने 5 करोड़ से ज़्यादा मानव-दिवस रोजगार सृजित किया है। यूएसबीआरएल परियोजना के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण पहलू 215 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों का निर्माण रहा है, इसमें एक सुरंग और 320 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। इस सड़क नेटवर्क ने स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, यूएसबीआरएल परियोजना में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सभी सुरंगों में वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए हैं। सभी सुरंगों में संभावित आग की घटनाओं से तुरंत निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अग्नि हाइड्रेंट और अग्निशामक यंत्रों सहित अग्निशमन प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 3 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में निकास सुरंगें भी बनाई गई हैं। इस परियोजना में कुल 66 किलोमीटर की निकास सुरंगें बनाई गई हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए, ढलान स्थिरीकरण पर उचित ध्यान दिया गया है और इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक भू-भागों के क्षरण और क्षति को रोकने के लिए, नीरी के दिशानिर्देशों और विस्तृत डिज़ाइन सलाहकारों के सुझावों के अनुसार ढलान

स्थिरीकरण हेतु व्यापक योजनाएं लागू की गई हैं। चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता का डिज़ाइन भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर और आईआईटी/दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। चिनाब पुल पर ढलान स्थिरता की स्वतंत्र जांच के लिए ऐसे कार्यों का अनुभव रखने वाली अन्य वैश्विक फर्मों को जिम्मेदारी दी गई थी। अंजी पुल पर ढलान स्थिरता का डिज़ाइन और प्रमाण-जांच का काम भी अनुभवी वैश्विक फर्मों द्वारा किया गया। इसके अलावा, चिनाब और अंजी खड्ड पुलों सहित कटरा-काजीगुंड नई रेल लाइन के निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा किया गया है। नीरी द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के आधार पर व्यापक सुरक्षा उपाय और शमन उपाय लागू किए गए हैं। सुरंग से निकली सामग्री के प्रबंधन हेतु, प्रकृतिक नालों में पानी छोड़ने से पहले, सुरंग के निकास द्वारों पर अवसादन टैंक बनाए गए हैं। जिन गांवों में रिवर्स पंपिंग के कारण प्राकृतिक जल स्रोत बाधित हो गए थे, वहां वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराए गए। सतही जल का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और मलबा यार्डों में कटाव को रोकने के लिए आवश्यक स्थानों पर उचित पंक्तिबद्ध नालियां और सीढ़ीदार ढलान बनाए गए।

सुरंग निर्माण के दौरान कंपन और पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम रखने के लिए नियंत्रित विस्फोट की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। कटरा-बनिहाल खंड की सभी सुरंगों में परिचालन चरण के दौरान भी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं। पूरी रेल परियोजना सुरंगों और खुले खंडों में ओवरहेड कंडक्टर प्रणाली के उपयोग से विद्युतीकृत की गई है। रेल परिवहन सबसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधन है, जो डीजल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है।

यद्यपि जैव विविधता संरक्षण के विशिष्ट उपायों को ईएमपी में रेखांकित किया गया है, समग्र पर्यावरणीय शमन प्रयास स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा में योगदान करते हैं। डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण गतिविधि के लिए स्थल तैयारी दिशानिर्देशों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाना और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन के लिए घास लगाना शामिल है। घाटी वाले हिस्से की शेष भारतीय रेल नेटवर्क के साथ सभी मौसमों के अनुकूल, विश्वसनीय और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी के साथ, पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। यूएसबीआरएल परियोजना (272 किलोमीटर) पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निर्मित की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रचलित 'जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1990' के अनुसार किया गया। भूमि अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कलेक्टर भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किया गया। भूमि स्वामित्व, संरचनाओं का मूल्यांकन, लाभार्थियों की पहचान, भूमि और संरचनाओं, वृक्षों आदि के लिए मुआवजे की गणना की गई। इस सम्बंध में पुरस्कार दिए गए और मुआवजे की राशि वितरित की गई। यूएसबीआरएल परियोजना के लिए अधिग्रहित कुल भूमि में 1559.48 हेक्टेयर निजी भूमि और 276.71 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस भूमि अधिग्रहण की पूरी राशि, यानी 816.21 करोड़ रुपये, सम्बंधित कलेक्टर भूमि अधिग्रहण के पास पहले ही जमा कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित लंबित दावों के समाधान की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 18 में पहले से ही शामिल है। रेलवे सम्बंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करता है। भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित सभी गतिविधियां, जैसे भूमि खोने वालों को मुआवजे की राशि का आकलन आदि, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य सरकार का राजस्व विभाग, रेलवे से मांग करने के बाद, भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देता है।